नई सोच, नया आयाम

RNI No. CHHHIN/2009/35020

जोहार छत्तीसगढ़

दैनिक हिन्दी

◆ वर्षः -14 ◆ अंकः 286 डाक पंजीयन 030/रायगढ़/2015-2017 ◆ मूल्यः 2 ₹ ◆ पृष्ठ : 4

धरमजयगढ़, बुधवार 24 अगस्त 2022

JOHAR CHHATTISGARH epaper for login www.joharchhattisgarh.in

पेज -3 पर बस्तर में कृमि से बचाव के लिये बच्चों को दी जाएगी एल्बेंडाजोल की .....

सीएम के जन्म दिन पर दीर्घायु की आहुती के साथ वस्त्र दान' पेज -4 पर

डामर घोटाले में इन चार अफसरों के खिलाफ होगा एफआईआर, सरकार ने दी मंजूरी

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित डामर घोटाले के मामले में पीडब्ल्यूडी के 4 अधिकारियों और कंसल्टेंसी कंपनी के खिलाफ स्नङ्घक्रदर्ज किया जायेगा। इस घोटाले को लेकर दोबारा दायर जनहित याचिका पर शासन की ओर से हाईकोर्ट में बताया गया है कि संबंधितों के खिलाफ जल्द एफआईआर दर्ज की जाएगी, शासन ने इसकी अनुमति दे दी है।

याचिका निराकृत करते हुए कोर्ट ने कहा है कि यदि याचिकाकर्ता शासन की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं होता है तो उसे दोबारा अदालत आने की छूट है।

बता दें कि वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष वीरेन्द्र पांडे ने सन् 2014 में डामर घोटाले के लिए जिम्मेदार अधिकारियों व अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि राज्य सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से 1200 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था, जिसमें 17 सड़कों के निर्माण में करीब 200 करोड़ रुपये अधिक का घोटाला किया गया है।

इस याचिका में दस्तावेजों के साथ जानकारी दी गई थी कि एक ही बिल लगाकर कई सड़कों के निर्माण के लिए डामर खरीदी और निर्माण कार्य दर्शा दिया गया था। अधिकारियों व ठेकेदारों की मिलीभगत से इसमें भ्रष्टाचार हुआ। सन् 2019 में इस याचिका को शासन के लिखित आश्वासन के बाद निराकृत कर दिया गया था।

समिति से कराई गई जांच

शासन के निर्देश पर एसीबी ने तीन अधिकारियों की एक समिति बनाई जिसे एक माह के भीतर घोटाले की जांच करके रिपोर्ट देनी थी। पर यह रिपोर्ट बहुत विलंब से तैयार हुई। पीडब्ल्यूडी ने मार्च 2022 में जांच प्रतिवेदन के साथ पत्र लिखकर एसीबी से कहा कि बेमेतरा से मुंगेली तक की बनाई गई 17 सड़कों में तत्कालीन परियोजना अधिकारी एससी त्रिवेदी, आरवाय सिद्दीकी, जे एम लुलु, कार्यपालन अधिकारी एन के जयंत तथा कंसल्टेंसी फर्म रेनारडेट एसए घोटाले के जिम्मेदार पाए गए हैं, इन पर कार्रवाई की जाए।

एसीबी ने दोबारा की जांच

एसीबी ने इस प्रतिवेदन के आधार पर पुनः जांच की और उक्त अधिकारियों तथा कंसल्टेंट कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए शासन से अनुमति मांगी। यह अनुमति नहीं मिली, तब पांडेय की ओर से हाईकोर्ट में दोबारा याचिका दायर कर कहा गया कि जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई में देर कर उन्हें परेशान किया जा रहा है। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट को शासन की ओर से बताया गया कि एसीबी को स्नङ्घक्रदर्ज करने की अनुमति दे दी गई है। एफआईआर शीघ्र दर्ज की जाएगी।

कार और ट्रक में टक्कर, 2 दोस्तों की मौत

नाश्ता करने निकले थे 3 छात्र, तभी हुआ हादसा; एक की हालत गंभीर

दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में भीषण सड़क हादसा हो गया है। यहां कार और ट्रक में जबरदस्त टक्कर हो गई है। जिसमें 2 छात्रों की मौत हो गई है। वहीं एक छात्र की हालत गंभीर बनी हुई है। तीनों दोस्त कार में बैठकर कहीं नाश्ता करने जा रहे थे, तभी ये हादसा हो गया है। हादसा स्मृति नगर चौकी क्षेत्र में हुआ है।

जानकारी के मुताबिक, सुबह के वक्त कैलाश नगर निवासी सौरभ यादव अपने दो दोस्त समीर कुजूर और एम .कामेश के साथ नाश्ता करने के लिए बाईपास रोड स्थित किसी होटल में जा रहे थे। ये अभी बाईपास के पास पहुंचे थे, उसी वक्त दूसरी तरफ से तेज रफ्तार ट्रक आ गया। इसके बाद दोनों गाड़ियों में टक्कर हो गई।

हादसे के बाद कार सवार तीनों छात्र कार में ही फंस गए थे। वहीं ट्रक चालक गाड़ी छोड़कर भाग निकला। आस-पास के लोगों ने जैसे ही इस घटना को देखा वे मौके पर पहुंचे। पुलिस को भी इसकी खबर दी गई थी। खबर मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और तीनों को कार से निकालने का प्रयास किया गया। बताया गया कि हादसा इतना जबरदस्त था कि तीनों काफी देर तक अंदर फंसे रहे।

एक नजर

जुआरियों एवं सटोरियों के खिलाफ कार्रवाई

रायपुर । राजधानी पुलिस ने जुआरियों एवं सटोरियों के खिलाफ कार्रवाई की है।

मिली जानकारी के अनुसार आरंग पुलिस के टीम ने अकोली रोड के पास जुआ खेलते आरोपी खिलेश जलक्षत्री सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से तासपत्ती सहित नकदी 1350 रुपए जब्त किया है। वहीं पुरानी बस्ती पुलिस ने कंकालीपारा चौक में जुआ खेलते आरोपी संतोष दुबे 47 वर्ष सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन सभी के पास से तासपत्ती सहित नकदी 13400 रुपए जब्त किया है। इसी तरह खमतराई पुलिस ने सट्टा-पट्टी लिखते आरोपी दीपक वर्मा 29 वर्ष व रामसिंह सिन्हा 53 वर्ष को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन दोनों के पास से 900 रुपए जब्त किया है। मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की है।

एटीएम के पास खड़ी बाइक पार

रायपुर । स्टेशन रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम के पास खड़ी बाइक को अज्ञात चोर ने पार कर दिया। प्रार्थी की शिकायत पर गंज थाना पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।

मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी प्रमोद कुमार 53 वर्ष शुक्रवारी बाजार गुढियारी का रहने वाला है। बताया जाता है कि वह अपनी बाइक क्रमांक ओआर 17 बी 9650 को स्टेशन रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक एटीएम के पास खड़ी किया था।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केन्द्रीय गृहमंत्री सहित अनेक जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को जन्मदिन की दी बधाई

प्रदेश भर से लोगों ने मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर दी बधाई

रायपुर। बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे भी मुख्यमंत्री को बधाई देने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के जन्मदिवस पर आज राष्ट्रपति सुश्री द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति श्री जगदीश धनखड़, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला, केन्द्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह, केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके, कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी सहित अनेक केन्द्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्रियों, राष्ट्रीय नेताओं और राष्ट्रीय मीडिया के प्रतिनिधियों ने विभिन्न माध्यमों से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को जन्मदिन की बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।

राष्ट्रपति सुश्री मुर्मू, प्रधानमंत्री श्री मोदी, लोकसभा अध्यक्ष श्री बिड़ला और राज्यपाल सुश्री उइके ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री श्री बघेल को बधाई देते हुए उनके स्वस्थ और सुदीर्घ जीवन की कामना की है।

बेरोजगारी को लेकर भाजयुमो का हल्लाबोल आज

रायपुर। बेरोजगारी को लेकर भाजयुमो द्वारा राज्य सरकार के खिलाफ 24 अगस्त को होने वाले हल्ला बोल की तैयारी भाजपा में जोर-शोर से चल रही है। दो-तीन दिन से भाजपा नेताओं द्वारा लगातार बैठकें ली जा रही है। प्रदर्शन में प्रदेशभर से एक लाख भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है । रायपुर से ही 25 हजार कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटाने के लिए चारों विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को लक्ष्य दिया गया है। सबसे अधिक दक्षिण विधानसभा से 10 हजार कार्यकर्ताओं को जुटाने की कोशिश है। वहीं प्रदर्शन में शामिल होने के लिए प्रदेशभर से भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ता आज यानी मंगलवार तक राजधानी पहुंच जाएंगे। इन सभी के ठहरने और खाने की व्यवस्था के लिए भाजपा ने 30 के करीब होटल, लॉज और धर्मशालाएं बुक कर रखी है।

हल्ला बोल प्रचार रथ रवाना

प्रदर्शन के लिए भाजपा ने राजधानी रायपुर के विधान सभा क्षेत्र में प्रचार के लिए हल्ला-बोल प्रचार रथ रवाना किया। आठ प्रचार रथ को सोमवार को प्रदेश सहप्रभारी नितिन नवीन और भाजपा नेताओं ने हरी झंडी दिखाकर रवाना। जिला स्तर पर भाजयुमो द्वारा हल्ला बोल प्रचार रथ भी चलाया जा रहा है।

नवीन ने कांग्रेस पर साधा निशाना

प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने बेरोजगारों के साथ अन्याय किया है। घोषणा पत्र में किए गए वादे आज तक पूरा नहीं किया। न तो रोजगार उपलब्ध कराया और न ही बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपए दिया। कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदेशभर के युवाओं में आक्रोश है। 2023 में प्रदेश के युवा ही कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेकेंगे।

भारी मात्रा में नशीले पदार्थों को जलाया

बिलासपुर रेंज के जिलों में किया गया था जब्त, कोरबा के बालको विद्युत संयंत्र में किया गया नष्ट

कोरबा/बिलासपुर। बिलासपुर रेंज के विभिन्न थाना-चौकियों में जब्त 4 टन से अधिक गांजे को बालको (कोरबा) के विद्युत संयंत्र में नष्ट कर दिया गया। इसे कोयले के साथ मिलाकर विद्युत उत्पादन में उपयोग लिया गया और लगभग 5 मेगावाट बिजली इस मिश्रण से उत्पादित की गई। इसके अलावा दूसरे नशीले पदार्थों को भी यहां जलाकर नष्ट कर दिया गया। मादक पदार्थों को नष्ट करने के लिए बिलासपुर रेंज स्तर पर 4 सदस्यीय हाई पावर ड्रग डिस्पोजल कमेटी का

गठन किया गया है। कमेटी ने बिलासपुर रेंज के कोरबा, जांजगीर-चांपा, रायगढ़ और मुंगेली जिलों के नष्टीकरण योग्य कुल 190 केस में जब्त 4.111 टन गांजा, 131 पौधे, 14,554 टैबलेट, 3,600 बोतल कफ सिरप, 2 ग्राम ब्राउन शुगर और 347 नशीले इंजेक्शन को जलाकर खत्म किया।

छत्तीसगढ़ के एक स्कूल में 77 लाख का घोटाला

एक टीचर को 11 महीने में 22 बार एरियर; जमा किए अलग-अलग तारीख के बिल

बिलासपुर। अभी तक आपने सरकारी कार्यालयों में लाखों रुपए की हेराफेरी के बारे में पढ़ा और सुना होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ के एक स्कूल में 77 लाख रुपए का घोटाला सामने आया है। प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी स्कूल में इतनी बड़ी रकम की हेराफेरी की गई है और शासन को चूना लगाया है। यह मामला है एशिया के सबसे बड़े ब्लॉक बिल्हा के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बेलतरा का।

यहां पदस्थ प्राचार्य और क्लर्क ने ट्रेजरी के अधिकारियों व

कर्मचारियों से मिलीभगत कर एक लेक्चरर को बतौर एरियर्स 77 लाख रुपए का बिल बनाकर भुगतान भी कर दिया। इस गड़बड़ी का खुलासा विभागीय ऑडिट और प्राचार्य की शिकायत से हुआ, तब अफसरों की नींद उड़ गई। विभाग ने क्लर्क को सस्पेंड करने के साथ ही लेक्चरर को रिकवरी के लिए नोटिस जारी किया और तीन सदस्यीय जांच कमेटी से जांच कराई। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अब प्राचार्य, लेक्चरर और क्लर्क को नोटिस जारी कर उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने की तैयारी है। दरअसल, पूरा मामले बेलतरा स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल में साल 2018 से 2019 के बीच महज 11 माह 20 दिन के भीतर का है। तब वहां प्राचार्य नरेंद्र राठौर अवकाश पर थे। उन्होंने लेक्चरर पीएल मरावी को प्राचार्य का प्रभार दिया गया था। साथ ही पीएल मरावी को ट्रांजेक्शन का अधिकार भी दिया।

राजनीति.. छत्तीसगढ़ बीजेपी का खुला चैलेंज

नितिन नबीन अफसरों से बोले-मेरे युवाओं पर दबंगई दिखाई तो भारी नुकसान चुकाना पड़ेगा

रायपुर। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के तेवर तेज होते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन ने अफसरों को चैलेंज कर दिया है।

उन्होंने कहा कि मैं छत्तीसगढ़ के प्रशासन को अफसरों को चुनौती देता हूं, कृपया करके मेरे युवाओं को किसी भी प्रकार से परेशान करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से ये आंदोलन दूसरा रूप ले लेगा। हमारे आंदोलन को लोकतांत्रिक तरीके से चलने दें। अगर प्रशासन के लोग दबंगई करेंगे तो भारी नुकसान चुकाना पड़ेगा। दरअसल ये बातें उन्होंने 24 अगस्त को रायपुर में होने जा रहे भाजपा के हल्ला बोल कार्यक्रम को लेकर कहीं हैं। सोमवार देर शाम भाजपा कार्यालय में कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर एक बैठक के बाद प्रदेश के अफसरों पर नितिन नबीन ने तीखे प्रहार किए। कहा कि भाजपा युवा मोर्चा ने जो

प्रदेश में आंदोलन किए, वो अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है। हमारे आंदोलन को लोकतांत्रिक तरीके से करने में प्रशासन सहयोग करे। रायपुर का जिला प्रशासन कार्यक्रम की अनुमति को लेकर ना-नुकुर कर चुका है। पिछले दो दिनों में कई घंटों की बैठकें भाजपा के नेता और प्रशासन के अधिकारी कर चुके हैं। पहले कार्यक्रम की अनुमति को लेकर असमंजस के हालात बने। फिर कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर भूरे ने अफसरों से कह दिया कि अनुमति के बाद ऐन मौके पर किसी ने कार्यक्रम में कोई बदलाव किया तो सख्त कार्रवाई करेंगे। इस वजह आंदोलन के पहले से ही भाजपा और जिला प्रशासन के बीच खींच-तान है। मीडिया से बात करते हुए नितिन नबीन ने कहा-24 अगस्त की तारीख कांग्रेस याद रखेगी। इस दिन के बाद से कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। 24 को कार्यक्रम होने के अगले दिन से कांग्रेस का काउंट-डाउन शुरू हो जाएगा।

रायपुर में महिला का मर्डर

कमरे में सोने गई महिला की सुबह निकली लाश, तकिए से मुंह दबाकर हत्या की आशंका

रायपुर। रायपुर के खमतराई इलाके में एक महिला की हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में अनजान लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। इस मामले को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।

महिला की हत्या किसने की यह पता नहीं चल सका है, परिजनों पर पुलिस को शक है सभी से पूछताछ की जा रही है।

मामले में अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक महिला की

मौत सोमवार को हो चुकी थी। सुबह घर वालों को कमरे से महिला की लाश मिली।

पहले तो मौत हार्ट अटैक जैसे कारणों से होने जैसा मामला लगा, मगर अब पुलिस की जांच में नया मोड़ आया है । शार्ट पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि महिला पर अटैक हुआ और सांस रुक जाने की वजह से उसकी मौत हुई है। 31 साल की सरस्वती राठौर जांजगीर की रहने वाली थी। वह शिव विहार सेक्टर 3 शिवानंद नगर में अपने भतीजे रंजीत राठौर और पति राजू राठौर के साथ रहती थी। महिला का पति राजू फैक्ट्री में काम किया करता था । 21 अगस्त की रात नाइट ड्यूटी होने की वजह से फैक्ट्री चला गया । जानकारी के मुताबिक सरस्वती और उसका भतीजा रंजीत घर पर थे। दोनों ने रात में खाना खाया इसके बाद अपने अपने कमरे में सोने चले गए । महिला के भतीजे रणजीत ने पुलिस को बताया है कि चाची ने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद नहीं किया था।

आर्थिक विकास की दरकार, तंग चल रही वित्तीय स्थिति और ज्यादा बिगाड़ रही

बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिजली क्षेत्र की प्रगति को प्रभावित करने वाले एक महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ देश का ध्यान खींचा है। आर्थिक विकास में बिजली क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए, उन्होंने राज्य सरकारों से बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) का बकाया भुगतान करने की अपील की है। डिस्कॉम का नुकसान और बकाया-एक गंभीर समस्या है। पॉवर फाइनेंस कॉरपोरेशन की 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 29 में डिस्कॉम घाटे में चल रही हैं।

2019-20 तक, डिस्कॉम का कुल घाटा पांच लाख करोड़ रुपये पहुंच गया, और उनकी उधारी वर्ष 2010-20 की तुलना में ढाई गुना बढ़ गई। कोरोना महामारी के दौरान डिस्कॉम के नुकसान और कर्ज में और बढ़ोतरी हो गई है। डिस्कॉम के संकट का एक प्रमुख कारण दो लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का बकाया है, जिसमें सरकारी विभागों और राज्य सरकारों से लंबित भुगतान/सब्सिडी की हिस्सेदारी 70 प्रतिशत, और निजी उपभोक्ताओं (मुख्य रूप से घरेलू कनेक्शन) का बकाया 30 प्रतिशत है।

इसे हल करने के लिए राज्यों और डिस्कॉम को इन तीन प्रमुख उपायों पर केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए। पहला, छह राज्यों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जिन पर डिस्कॉम के लंबित भुगतान का तीन-चौथाई हिस्सा बकाया है। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। सरकारी विभागों से डिस्कॉम के बकाये का निपटान करने के लिए, संबंधित राज्य अपने बजटीय आवंटन में से चरणबद्ध रूप से अग्रिम कटौती करने के बारे में विचार कर सकते हैं। दूसरा, राज्यों को अपने सीमित वित्तीय संसाधनों के कुशल उपयोग और बिजली को जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करने की संस्कृति बनाने के लिए बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने और लक्षित करने की दिशा में काम करना चाहिए। काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट ऐंड वॉटर (सीईईडब्ल्यू) के अध्ययन के अनुसार, सात राज्यों को छोड़कर, 2016-20 के दौरान अधिकांश राज्यों में बिजली दर (टैरिफ) में सब्सिडी पर निर्भरता में बढ़ोतरी

बिजली सुधार में राज्यों की भूमिका अहम

भारत, पहले ही कई तरीकों से ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन के मामले में अपने नेतृत्व को दुनिया के सामने प्रदर्शित कर चुका है। इसमें रिकॉर्ड समय में गांवों और घरों का विद्युतीकरण, और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा उत्पादक बनने जैसी उपलब्धियां शामिल हैं।

हुई है।

मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब और कर्नाटक उन शीर्ष राज्यों में शामिल हैं, जहां डिस्कॉम अपने कुल राजस्व के 30 प्रतिशत या उससे ज्यादा हिस्से के लिए टैरिफ सब्सिडी पर निर्भर हैं। बिजली पर सब्सिडी में बढ़ोतरी, राज्यों की पहले से तंग चल रही वित्तीय स्थिति और ज्यादा बिगाड़ रही है। इसलिए, राज्यों को केवल कमजोर और योग्य उपभोक्ताओं को ही सब्सिडी देनी चाहिए। इसके अलावा, राज्यों को पीएम-कुसुम योजना के तहत किसानों के बीच सोलर पंप जैसे सिंचाई के साधनों को बढ़ावा देना चाहिए।

तीसरा, डिस्कॉम को हाल ही में शुरू की गई 'रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर' (आरडीएस) योजना के तहत उपलब्ध विभिन्न वित्तीय और तकनीकी मदद का पूरी सक्रियता के साथ लाभ उठाना चाहिए। तीन लाख करोड़ रुपये की इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2025 तक डिस्कॉम को अपना घाटा 12-15 प्रतिशत तक घटाने में मदद करना है। इस लक्ष्य को पाने के लिए डिस्कॉम को अपने सभी बिजली कनेक्शन के साथ स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मजबूत करने की जरूरत है।

भारत, पहले ही कई तरीकों से ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन के मामले में अपने नेतृत्व को दुनिया के सामने प्रदर्शित कर चुका है। इसमें रिकॉर्ड समय में गांवों और घरों का विद्युतीकरण, और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा उत्पादक बनने जैसी उपलब्धियां शामिल हैं। अब हमारे पास और भी महत्वाकांक्षी लक्ष्य हैं। अब हम 2030 तक 500 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा की उत्पादन क्षमता स्थापित करना, और 2070 तक नेट-जीरो (कार्बन न्यूट्रल) अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। इन लक्ष्यों को पाने के लिए, राज्यों को निश्चित तौर पर केंद्र के साथ मिलकर बिजली क्षेत्र को स्वस्थ व मुश्किलों को सहने में सक्षम बनाना होगा।

शालू अग्रवाल

संपादकीय

बिलकीस बानो के सवाल

बलात्कारियों या हत्यारों के प्रति नरम रुख अपनाने वाला समाज असल में धीरे-धीरे खुद को सभ्यता से दूर करता चला जाता है। इसके दुष्परिणाम सभी नागरिकों को भुगतने पड़ते हैं। गुजरात के 2002 के दंगों की एक प्रमुख शिकार बिलकीस बानो ने अगर कहा है कि भारतीय न्याय व्यवस्था से संरक्षण पाने का उनका भरोसा टूट गया है, तो इसके लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। जब किसी देश में न्याय और अपराध की व्याख्या और उन पर अमल ठोस साक्ष्यों के आधार पर नहीं, बल्कि राजनीतिक- वैचारिक हितों के आधार पर होने लगे, तो उसकी वजह से उत्पीड़ित लोगों से आखिर और क्या अपेक्षा की जा सकती है? बिलकीस बानो का मामला ऐसा नहीं है, जिसमें राहत पाने वाले लोग आरोपी हैं। बल्कि वे सजायाफ्ता हैं, जिनके दंड की पुष्टि सर्वोच्च न्यायालय से हुई थी। फिर गुजरात सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के दिन उन अपराधियों की सजा माफी खुद अपने इस दिशानिर्देश को तोड़ते हुए दी कि बलात्कार और अन्य जघन्य अपराध के दोषी लोगों को सजा माफी नीति का लाभ नहीं मिलेगा। एक दशक पहले सजा माफी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ दिशानिर्देश तय किए थे। तब उसने ऐसे सभी मामलों को न्यायिक समीक्षा के दायरे में ला दिया था। क्या पहली दृष्टि में यह नहीं लगता कि बिलकीस बानों के मामले में लिया गया फैसला तब न्यायालय जिन भावनाओं से प्रेरित था, उनका भी उल्लंघन है? सजा माफी की इस घटना आज देश के सामने फिर से यह यक्ष प्रश्न खड़ा कर दिया है कि क्या भारत आधुनिक न्याय व्यवस्था और कानून के राज के सिद्धांत से चलेगा- या यहां अपराध, न्याय और कानून की धारणाएं सत्ता पक्ष के हितों से तय होंगी?

जनता के पैसे के इस्तेमाल पर बहस कब? मुफ्त की रेवड़ियों पर तुमुल कोलाहल

राजनीति के मैदान में मुफ्त की रेवड़ियों पर तुमुल कोलाहल है। संकेतों, पूर्व धारणाओं और आरोपों की भीषण प्रतिद्वंद्विता चल रही है। रेवड़ियों के मामले में कोई भी राजनीतिक पार्टी पाक-साफ होने का दावा नहीं कर सकती। इस मामले में राजनीतिक संवाद की जरूरत तो है, पर नारेबाजी और शब्दाडंबरों के जरिये वास्तविक संवाद का रास्ता रोक दिया गया है। मौजूदा स्थिति व्यापक विमर्श की मांग करती है।

इस मुद्दे पर जनता के ध्यान को तात्कालिक समझ लेने और रेवड़ियों को सिर्फ चुनावी लाभ तक सीमित मान लेने की गलती हो सकती है। यह परिभाषित करने की जरूरत है कि मुफ्त की रेवड़ियां क्या हैं। इसकी लागत और इसके सांविधानिक कवच पर भी बहस होनी चाहिए। जनता की चिंता कई बार सार्वजनिक खर्च और करदाताओं का पैसा खर्च करने के मामले में सरकारी दूरदर्शिता की कमी के कारण पैदा गुस्से के रूप में भी सामने आती है।

करीब एक दशक पहले ही राज्य सरकारों ने खर्च के मामले में केंद्र सरकार को पीछे छोड़ दिया था। वर्ष 2016 से 2021 तक केंद्र और राज्य सरकारों का कुल खर्च 37.06 करोड़ रुपये से बढ़कर 64.70 लाख करोड़ रुपये हो गया। इस दौरान राज्य सरकारों का खर्च 23.60 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 42.11 लाख करोड़ रुपये

स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्याप्त बदहाली का उदाहरण हाल ही में मध्य प्रदेश में दिखा, जहां एक सरकारी अस्पताल में एक बुजुर्ग महिला के घायल सिर की ड्रेसिंग कंडोम के पैकेट से कर दी गई!

हो गया। इस धनराशि का किस तरह इस्तेमाल किया गया? आम धारणा यह है कि चुने हुए विधायक अपनी जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या चुने हुए जनप्रतिनिधियों के पास इतना समय और ऐसी सोच है कि वे करदाताओं का पैसा खर्च करने के मुद्दे पर बहस करें? राज्य सरकारों का अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि जनप्रतिनिधियों के पास अपनी जनता के बारे में सोचने, सत्तारूढ़ सरकारों के दावों का खंडन करने, सरकारी फंड पर बहस करने और योजनाओं को लागू करने का समय न के बराबर है। पीआरएस लेजिस्लेटिव का अध्ययन बताता है कि वर्ष 2016 से 2021 के बीच राज्य विधानसभाओं की साल में औसत 25 दिन ही बैठकें हुईं।

वर्ष 2021 में सभी राज्यों का कुल खर्च 42.11 लाख करोड़ रुपये था-यानी पिछले साल राज्य सरकारों का प्रति घंटे का खर्च 480 करोड़ और एक दिन का खर्च 11,537 करोड़ रुपये था। पिछले साल राज्य विधानसभाओं की बैठक औसतन 25 दिन हुईं- जो 2016 के सालाना 30 दिन से कम है। बदतर यह कि 29 में से 17 राज्य विधानसभाओं की पिछले साल 20 दिन से भी कम, जबकि पांच राज्य विधानसभाओं की 10 दिन से भी कम बैठकें हुईं! कर्नाटक, ओडिशा, मणिपुर, पंजाब और उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं में विभिन्न सत्रों में एक तय संख्या में बैठक करने का नियम है।

पर 2016 से 2021 तक कहीं भी इस नियम का पालन नहीं हुआ। पंजाब का ही उदाहरण लीजिए। वर्ष 2021 में इसका ऋण-जीएसडीपी (राज्य की जीडीपी) अनुपात 53.3 फीसदी, वित्तीय घाटा 4.3 प्रतिशत था और राजस्व का पांचवां हिस्सा ब्याज चुकाने में खर्च हुआ था। जाहिर है, राज्य की बदतर वित्तीय स्थिति ध्यान देने की मांग करती थी।

पंजाब विधानसभा की साल में 40 दिन बैठक होने का नियम है। वर्ष 2021 में राज्य में विधानसभा की 11 दिन बैठकें हुई, जबकि 2016 से 2021 के बीच पंजाब विधानसभा में सालाना औसतन 14 दिन बैठकें हुईं। जनसंख्या के मामले में देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का उदाहरण लीजिए।

शंकर अय्यर

मिला जुला

2024 में मोदी बनाम केजरीवाल? गुजरात चुनाव तय करेगा सूरत-ए हाल

नई दिल्ली। दिल्ली में शराब घोटाला मामले ने आम आदमी पार्टी सरकार को मुश्किल में डाल दिया है. डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिसके चलते उनपर सीबीआई का शिकंजा कस गया है.

विपक्ष में बैठी बीजेपी इसे लेकर हमलावर है तो आम आदमी पार्टी इस पूरी कार्रवाई को बदले की भावना बताते हुए 2024 के लिए नरेंद्र मोदी बनाम केजरीवाल का एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रही है. हालांकि केजरीवाल का नेशनल ड्रीम तभी संभव है, जब आम आदमी पार्टी गुजरात के चुनावी दंगल में बीजेपी को दमदार चुनौती दे पाए।

मोदी बनाम केजरीवाल नेरेटिव कैसे शुरू हुआ?

मोदी बनाम केजरीवाल का नेरेटिव आम आदमी पार्टी पहले से ही सेट कर रही थी, लेकिन जब शराब घोटाले में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर रेड डाली, तो AAP नेताओं ने इसे भुनाने में देरी नहीं की.

सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि जब से पंजाब में आप ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, लोग कहने लगे हैं कि उन्हें एक विकल्प मिल गया है. देश की राजनीति मोदी बनाम केजरीवाल बन गई है। बीजेपी केजरीवाल से डर गई है, इसलिए उनके मॉडल को खत्म करना चाहती है।

विधानसभा चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे बढ़े, 27-28 अगस्त को भुज-कच्छ जाएंगे

खुद मनीष सिसोदिया ने भी इसी नेरेटिव को आगे बढ़ाते हुए सीबीआई जांच को 2024 के चुनाव से जोड़ दिया. उन्होंने कहा कि 2024 का चुनाव मोदी बनाम केजरीवाल ही होने वाला है. केजरीवाल को रोकने के लिए, उन्हें डराने के लिए केंद्र ऐसे हथकंडे आजमा रहा है. लेकिन उसके तमाम प्रयासों के बावजूद केजरीवाल राष्ट्रीय स्तर पर एक विकल्प के रूप में उभरे हैं. सवाल ये है कि क्या 2024 के चुनाव को मोदी बनाम केजरीवाल बनाना आम आदमी पार्टी के लिए इतना आसान है? क्या विपक्ष मोदी के खिलाफ केजरीवाल को अपना पीएम उम्मीदवार मानेगा? मोदी को टक्कर देने लायक कद केजरीवाल कैसे हासिल करेंगे? इन सवालों का सही-सही जवाब पाने के लिए गुजरात चुनाव के नतीजों का इंतजार करना होगा.

गुजरात में क्या है आप की रणनीति?

आम आदमी पार्टी इस समय गुजरात चुनाव में उसी रणनीति पर काम कर रही है, जिसके दम पर पहले दिल्ली और फिर पंजाब में उसने सरकार बनाई. AAP मॉडल के चार बड़े स्तंभ हैं- अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, मुफ्त बिजली और युवाओं को रोजगार. गुजरात चुनाव में AAP ने इन्हीं पहलुओं को अपनी 'गारंटी' बताया है जो वो सरकार बनते ही देने की बात कर रही है. यहां सबसे बड़ी घोषणा फ्री बिजली वाली है क्योंकि इसी के दम पर पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी को प्रचंड जनादेश दिया. अब गुजरात में भी ये AAP की पहली गारंटी है। वहीं, गुजरात में युवाओं को साधने के लिए अरविंद केजरीवाल ने रोजगार को लेकर बड़ा वादा किया है. उनकी तरफ से जोर देकर कहा गया है कि सरकार बनते ही वे 10 लाख सरकारी नौकरी निकालने वाले हैं, ऐसी योजना तैयार करेंगे जिससे सभी बेरोजगारों को रोजगार मिल सके।

बारिश और बाढ़ ने कर दिया बेहाल

नई दिल्ली। लगातार हो रही बारिश और बाढ़ के चलते विभिन्न राज्यों में हालात भयावह हो चुके हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत विभिन्न जिलों में सोमवार को भी हुई भारी बारिश के चलते यहां मौसम विभाग द्वारा रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। एमपी के विभिन्न जिलों में सोमवार को स्कूल भी बंद रहे।

उड़ीसा

उड़ीसा में बाढ़ के चलते करीब 8 लाख लोगों को अपना घर-बार छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा है। यहां लगातार हो रही बारिश के चलते बिजली और पानी की सप्लाई बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है।

हिमाचल प्रदेश

बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हिमाचल प्रदेश में सोमवार को मरने वालों की संख्या बढ़कर 32 पहुंच गई। इसमें से छह लोगों का अभी तक पता नहीं चल सका है। वहीं इस आपदा में कुल 12 लोग घायल हुए हैं।

उत्तराखंड

उत्तराखंड में भी बादल फटने की कई घटनाएं हो चुकी हैं। इसके चलते बाढ़ और लैंडस्लाइड के मामले सामने आए हैं और जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। नदियां उफान पर हैं। कई पुल टूट गए हैं। बाढ़ का पानी लोगों का घरों में घुस गया है। कई गांवों से लोगों को निकालना पड़ा है।

मध्यप्रदेश

मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में सोमवार को भी भारी बारिश होती रही। यह लगातार तीसरा दिन है जब बारिश ने इस प्रदेश के बेहाल कर रखा है। बारिश के साथ तेज हवाओं ने प्रदेश की राजधानी भोपाल में कई पेड़ों का उखाड़ डाला। इसके अलावा कई इलाकों में बिजली सप्लाई भी बाधित हुई है।

राजस्थान, झारखंड और उत्तर प्रदेश

राजस्थान में पिछले 24 घंटों में हुई तेज बारिश ने कोटा और कुछ अन्य इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। इसके चलते निचले इलाकों में पानी भर गया है। कोटा बैराज से अभी तक करीब 2.76 लाख क्यूसेक पानी निकाला जा चुका है। अभी भी कोटा, झालावाड़, बूंदी, बारां, चित्तौड़गढ़, सवाईमाधोपुर, दौसा और करौली के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई है।

आनंद शर्मा को मनाने में जुटी कांग्रेस, राजीव शुक्ला ने घर पर मुलाकात कर कहा, नाराजगी दूर की जाएगी

शिमला। कांग्रेस ने हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए गठित संचालन समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले अपने वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा को मनाने की कवायद तेज कर दी है। कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश के प्रभारी महासचिव राजीव शुक्ला ने सोमवार को यहां शर्मा के आवास पर उनसे मुलाकात की और उनकी नाराजगी को लेकर उनसे गहन बातचीत कर कहा कि उनकी शिकायत से पार्टी नेतृत्व को अवगत कराया जाएगा और उनकी जो भी नाराज़गी है उसे दूर किया जाएगा।

संचालन समिति से दिया था इस्तीफा : शर्मा ने रविवार को हिमाचल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गठित पार्टी की संचालन समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। उनका कहना था कि उन्हें नजरअंदाज कर अपमानित किया जा रहा है इसलिए उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष को इस्तीफा भेजा है। शर्मा कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं के समूह त्न-23 के प्रमुख नेता हैं। पार्टी के असंतुष्ट नेता पार्टी की मजबूती के लिए पार्टी नेतृत्व में है बदलाव की मांग कर रहे हैं।

पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी को लेकर बीजेपी विधायक टी राजा गिरफ्तार, हैदराबाद में भारी प्रदर्शन

हैदराबाद में पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करने वाले तेलंगाना से बीजेपी विधायक टी राजा को हैदराबाद सिटी टास्कफोर्स और शाहीनयथगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. दरअसल तेलंगाना से बीजेपी विधायक टी राजा के द्वारा दिए विवादित बयान के बाद मामला गर्मा गया है. हैदराबाद में उनके इस बयान के खिलाफ कल शाम से ही प्रदर्शन जारी है. टी राजा पर आरोप है कि उन्होंने पैगम्बर को लेकर विवादित बयान दिया है. उन पर यह आरोप है कि स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के खिलाफ जारी बयान में पैंबम्बर के खिलाफ विवादित टिप्पणी की है. डीसीपी पी साई चैतन्य ने बताया कि पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

दिल्ली शराब नीति मामला-MHA का बड़ा ऐक्शन, तत्कालीन आबकारी आयुक्त आरव गोपी कृष्णा और उपायुक्त आनंद तिवारी सस्पेंड

नई दिल्ली। दिल्ली शराब नीति से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार देर शाम बड़ा ऐक्शन लेते हुए तत्कालीन आबकारी आयुक्त आरव गोपी कृष्णा और उपायुक्त आनंद तिवारी सस्पेंड कर दिया है। दिल्ली उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के संबंध में आबकारी विभाग के 11 अधिकारियों के खिलाफ 'गंभीर चूक' के लिए निलंबन और अनुशासनात्मक कार्यवाही

शुरू करने के कुछ दिनों बाद सोमवार को गृह मंत्रालय ने तत्कालीन आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्णा और उपायुक्त आनंद तिवारी को निलंबित कर दिया है। बता दें कि, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोपों की सीबीआई जांच की सिफारिश करने के बाद दिल्ली सरकार द्वारा इस साल जुलाई में नीति को वापस ले लिया गया था। इस मामले में 17 अगस्त को सीबीआई द्वारा दिल्ली के आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई थी।

नि:शुल्क हृदय उपचार से रवीना के चेहरे पर लौटी मुस्कान

चिरायु योजना के तहत 11 वर्षीय रवीना को मिला लाभ

जोहार छत्तीसगढ़-कांकेर।

कई बच्चे जन्म से ही कुछ बीमारियों के साथ पैदा होते हैं, कुछ अन्य किसी कारण से गंभीर बीमारी का शिकार हो जाते हैं। उचित उपचार न मिलने से बीमारियां उनके शरीर में धीरे-धीरे बढ़ती जाती हैं और गंभीर रूप ले लेती हैं। कम उम्र में ही बच्चों में हृदय सहित कोई अन्य गम्भीर रोग हो जाये तो उसका बचपन छिन जाता है, और यदि माता पिता आर्थिक रूप से कमजोर हो तो समस्या बढ़ जाती है।

ऐसी किसी अन्य विकार से ग्रसित बच्चों को बचाये रखने और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत चिरायु योजनाए पीड़ित बच्चों और उनके परिजन के लिये वरदान साबित हो रही है। जिले के भानुप्रतापपुर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम मुल्ला की रहने वाली 11 वर्षीय रवीना ताराम, जिसे जन्मजात हृदय रोग था। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम द्वारा संचालित चिरायु टीम को स्कूल में नियमित स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान रवीना में थकान और कमजोरी की समस्या मिली। तदुपरान्त उसे जिले में संचालित होने वाले विशेष शिविर में लाया गया, जिसमें हृदय रोग विशेषज्ञ द्वारा दिल में छेद की बीमारी बताई गई। यह जानकारी मिलते ही बिना देरी किये रवीना के हृदय का उपचार रायपुर में किया गया। सफलतापूर्वक नि:शुल्क उपचार मिलने से रवीना और उसके परिजन के चेहरे पर मुस्कान लौट आयी है। इसके लिये चिरायु टीम के डॉ. इमरान खान, डॉ. चेतन, डॉ. तेजस्वी परिहार का विशेष योगदान रहा। कलेक्टर प्रियंका शुक्ला के मार्गदर्शन में छ.ग. सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चिरायु योजना के अंतर्गतए आंगनबाड़ी, स्कूल और अन्य स्थानों पर चिरायु टीम द्वारा जांच केंद्र स्थापित कर बच्चों की स्क्रीनिंग की जा रही है। तदुपरान्त बच्चों में स्वास्थ्य की गंभीर समस्या को देखते हुये उनका चिन्हांकन कर नि:शुल्क उपचार कराया जा रहा है। समय पर उचित लाभ मिलने से जिले के जरूरतमंद बच्चों की जिंदगी रौशन हो रही, साथ ही लाभान्वित बच्चे अब समाज में सामान्य बच्चों की तरह ही अपना भविष्य गढ़ रहे हैं। इस सम्बंध में सीएमएचओ डा. जेएल उईके ने बताया श्चिरायु योजना के तहत चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा चिन्हित स्थानों पर स्क्रीनिंग की जाती है। बच्चों की स्क्रीनिंग हेतु जांच केंद्र लगाए जाते हैं। बच्चों की प्री स्क्रीनिंग की जाती है जिसमें आँख से कम दिखाई देना, कानों से कम सुनाई देना, विटामिन की कमी, एनीमिया, हृदय रोग, जैसी बीमारियों की पहचान कर उनका इलाज किया जाता है। कोई बच्चा गंभीर स्थिति में है तो उसे टीम द्वारा तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल भेज दिया जाता है।

चिरायु योजना क्या है

चिरायु योजना छत्तीसगढ़ राज्य की स्वास्थ्य योजना है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत चिरायु योजना को 6 अगस्त 2014 से सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल में लॉन्च किया गया था, इसके बाद इससे सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ के लिए लॉन्च किया गया। योजना के अंतर्गत 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों की स्क्रीनिंग की जाती है। बच्चे में कोई बीमारी पाई जाती है तो उसका नि:शुल्क इलाज किया जाता है। बच्चों की स्क्रीनिंग के लिए चिरायु टीम अलग-अलग जगह पर जाकर जांच करती है।

एक नजर

अमानक खाद्य पदार्थों की बिक्री पर नकेल कसने की कवायद

खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के उपसंचालक व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने ली कार्रवाइयों की जानकारी

कवर्धा । बारिश के मौसम के चलते लोगों के खान-पान पर विशेष ध्यान रखा जाना आवश्यक होता है, इसके अलावा त्योहार के सीजन में डिमांड बढ़ने के चलते मिलावटी मिठाइयों व अन्य खाद्य पदार्थों की बिक्री की संभावनाओं के मद्देनजर खाद्य पदार्थों के मानकों की जांच सम्बन्धी कवायद शुरू कर दी गई है। इस सम्बंध में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा किये जा रहे कार्रवाइयों का विस्तृत विवरण मंगाकर विभाग के उपसंचालक व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ सुजॉय मुखर्जी द्वारा जानकारी ली गई। उन्होंने इस दिशा में सभी सम्भव प्रयास बढाने के निर्देश भी दिए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जानकारी में बताया गया कि जनवरी 22 से कुल 63 खाद्य नमूना संकलित किया जा चुका है। इनमें से 19 नमूना मानक व 2 अमानक घोषित किया गया है। 42 नमूनों का जांच रिपोर्ट आना शेष है। अधिकारी ने जानकारी दी कि सिर्फअगस्त माह में ही 24 खाद्य नमूना संकलित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर व आवश्यकतानुसार अन्य राज्य स्थित प्रयोगशालाओं में भेजा जाता है। इसके अलावा चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के माध्यम से भी मौके पर खाद्य सामग्रियों की परीक्षण की प्राथमिक कार्रवाई की जाती है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधनियम 2006 विनिमय 2011 की धारा 2.4.2 के तहत खाद्य विश्लेषक द्वारा विश्लेषण रिपोर्ट 14 दिनों के भीतर भेजे जाने का प्रावधान है। प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अमानक स्तर के खाद्य पदार्थों के सम्बन्धित प्रकरण माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। डॉ मुखर्जी ने जिले में मिलावटी अथवा नकली खाद्य सामाग्री बेचकर लोगों के सेहत से खिलवाड़ करने वालों के सम्बंध में तत्काल जानकारी देने की अपील जिले की जनता से की है। उन्होंने कहा कि खान-पान की गड़बड़ी से सेहत बुरी तरह से प्रभावित होता है, इसलिए ऐसे अमानक खाद्य सामग्रियों की बिक्री पर रोक लगाया जाना आवश्यक है।

मंत्री अकबर से भेंट की यूरोप में तिरंगा फहराने वाली अंकिता गुप्ता ने

कवर्धा । यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट अलब्रुश पश्चिम 6542 मीटर और माउंट अलब्रुस पूर्व 6521 मीटर दोनो पर तिरंगा झंडा फहराने एवम राज्य सरकार के न्याय एवम सशक्तिकरण के छत्तीसगढ़ माडल को प्रदर्शित करने का रिकार्ड बनाने वाली सुश्री अंकिता गुप्ता ने आज प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्री मोहम्मद अकबर से भेंट की।श्री अकबर ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराने पर अंकिता गुप्ता को बधाई देते हुए उनकी उज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस अभियान में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तथा कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर द्वारा दिए गए सहयोग के लिए अंकिता गुप्ता ने आभार व्यक्त किया ।उल्लेखनीय है कि अंकिता गुप्ता के इस अभियान के लिए श्री मोहम्मद अकबर की अनुशंसा पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पांच लाख रुपए की राशि स्वीकृत की थी।

कांग्रेस ने मंहगाई के विरोध में लगाया चौपाल

जोहार छत्तीसगढ़-देवभोग।

कस्तूरबा आवासीय विद्यालय के नन्हें छात्राओं के साथ सीएम का जन्म दिन मनाया कांग्रेसियों ने। दीर्घायू के साथ ही चहूं ओर यश फैलने की कामना किया। देवभोग ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने आज सीएम भूपेश बघेल का जन्मदिन कस्तूरबा आवासीय विद्यालय के छात्राओ के साथ मिल कर मनाया। जिला पंचायत अध्यक्ष स्मृति ठाकुर की मौजूदगी मे ब्लॉक व जिला कांग्रेस संगठन के पदा धिकारियों ने केक काटे। छात्राओं को फल भी भेंट किया। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष भूपेंद्र मांझी ने कहा कि मुखिया स्वास्थ्य व चिरायु रहे सदा, क्योंकि उनके हर कदम जन कल्याण के लिए होता है। बहुत कम समय में हमारे सीएम ने उन सरकारी योजनाओं को गांव गरीब व किसान वर्ग के हर जरूरत मन्द तक पहुंचाने में सफल रहे हैं। पहले की योजनाएं बड़े बड़े ठेकेदार, पूंजीपति व उद्योगपतियों को झोली में जाति थी, पर भुपेश की सोंच ने इस परिपाटी को बदल दिया है। जिला महामंत्री अरुण मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस की भुपेश सरकार गरीब किसान की सरकार है। आयोजन में दुर्गा चरण अवस्थी, जिला उपाध्यक्ष, अरुण सोनवानी महामंत्री ब्लॉक, सूरज शर्मा जिला महामंत्री, प्रमेश अवस्थी ब्लॉक उपाध्यक्ष, ऋषिकेश ओंकार पात्र, रूपचंद नागेश, हरिशंकर नागेश, सूरज प्रधान, धनेश्वर यादव, शंकर नागेश, मुकेश बीसी, अनिल, तुलाराम समस्त पधाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित थे। महंगाई चौपाल में पांच प्रस्ताव पारित सीएम के जन्मदिन मनाने से पहले, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आव्हान पर ब्लॉक कांग्रेस ने आज बस स्टैंड चौक पर महंगाई चौपाल का आयोजन किया था। ब्लॉक व जिला पदाधिकारियों ने पहले तो महंगाई के विरोध में नारे लगाकर केंद्र के मोदी सरकार को जमकर कोसा, फि र चौपाल में खाद्य सामग्री से लेकर पेट्रोल डीजल, उर्वरक, घरेलू गैस, आयकर व पिछेल दो साल में मंहगाई में धकेल दिए गए आम जरूरत की चीजों के मूल्य घटाने के लिए प्रस्ताव पारित कर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजा।

सूचना फलक दरिगंवा से दारगांव सड़क के प्रारंभ में लगाया गया

कवर्धा । कार्यपालन अभियंता सह सदस्य सचिव परियोजना क्रियान्वयन इकाई कवर्धा श्री दीपक कुमार मिश्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की दरिगंवा से दारगांव सड़क की लंबाई 1.90 किलोमीटर का नवीनीकरण कार्य राशि 35.83 लाख रूपए निर्माण का स्वीकृति प्राप्त हुई है। उन्होंने बताया कि सड़क के प्रारंभ में (आर.डी. 0.00) में कार्य से संबंधित सूचना पटल लगा हुआ है। जिसमें सड़क की लंबाई, लागत, संधारण लागत एवं कार्य प्रारंभ दिनांक तथा ठेकेदार का नाम, पुल पुलियों एवं रिर्टनिंगवाल के संबंध में उल्लेख है। सूचना फ्लक सड़क के प्रारंभ में ही लगाया गया है।

बस्तर में कृमि से बचाव के लिये बच्चों को दी जाएगी एल्बेंडाजोल की गोली

जोहार छत्तीसगढ़-जगदलपुर।

राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के तहत आयोजित होने वाले कार्यक्रम की सफलता को लेकर जिले में तैयारियां प्रारंभ हो चुकी है। 9 सितम्बर को कृमि मुक्ति दिवस और 14 सितम्बर को कृमि गोली से वंचित बच्चों के लिये मॉपअप दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष राज्य के 24 जिलों के 84.27 लाख बच्चों एवं किशोर किशोरियों 1 से 19 वर्ष को कृमि से बचाव हेतु, एल्बेंडाजोल की गोली खिलाने का लक्ष्य रखा गया है।

इस सम्बन्ध में सीएमएचओ डॉ. आरके चतुर्वेदी ने बताया, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत जिले के 1 वर्ष से 19 वर्ष तक के बच्चों को कृमि से मुक्ति दिलाने के लिए एल्बेंडाजोल की गोली का सेवन कराया जाएगा। कृमि से बचाव हेतु 9 सितम्बर को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाएगा तथा छूटे हुए बच्चों के लिये 14 सितम्बर को मॉपअप दिवस के तहत कृमि से बचाव की गोली खिलाई जाएगी। सितम्बर माह में चलने वाले कार्यक्रम के लिये राज्य से प्राप्त गाइडलाइन के अनुसार बस्तर जिले के समस्त विकासखंड को दिशानिर्देश भी भेजे जा चुके है। इस वर्ष बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों एवं शासकीय विद्यालयों शासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालय, मदरसों, निजी स्कूलों, अनुदान प्राप्त निजी स्कूलों, महाविद्यालयों, तकनीकी शिक्षा संस्थानों में कृमिनाशक दवा दी जाएगी। 1 से 2 वर्ष तक के बच्चों को आधी गोली 200 एमजी चूर्ण बनाकर पानी के साथ, 2 से 3 वर्ष तक के बच्चों को 1 गोली पूरी तरह से चूर्ण बनाकर पानी के साथ तथा 4 वर्ष से 19 वर्ष तक के बच्चों को एक पूरी गोली 400 एमजी चबाकर के पानी के साथ सेवन कराया जाएगा। एल्बेंडाजोल की गोली बच्चों और बड़ों के लिए सुरक्षित है। दवा खाने के उपरांत यदि कोई प्रतिकूल प्रभाव हो तो प्रबंधन के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपचार की व्यवस्था भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा रहेगी। कृमि मुक्ति दिवस पर बीमार बच्चों या पहले से कोई अन्य दवाई ले रहे बच्चों को एलबेंडाजोल की गोली नहीं दी जाएगी।

इन 24 जिलों में चलेगा कार्यक्रम

बस्तर, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, दन्तेवाड़ा, नारायणपुर, कांकेर, बलौदाबाजार, बलरामपुर, बिलासपुर, धमतरी, गरियाबंद, गौरेला-पेंड्रा-मारवाही, जशपुर, कवर्धा, कोरबा, कोरिया, महासमुंद, मुंगेली, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव, सूरजपुर और सरगुजा।

10 लीटर महुआ शराब के साथ एक गिरफ्तार

सरायपाली । बलौदा पुलिस ने कोटद्वारी मोड़ पर बिक्री के लिए ग्राहक के इंतजार में खड़े तलाश रहे एक व्यक्ति को 10 लीटर महुआ शराब के साथ पकड़ा। आरोपी ने अपना नाम ग्राम मुंडपहार निवासी राजू चौहान बताया। आरोपी को 34 (2) के तहत न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। कार्रवाई में चौकी प्रभारी बलौदा, उपनिरीक्षक उदय राम साहू, प्रधान आरक्षक पंकज बाग, आरक्षक सुभाष यादव, आरक्षक संदीप प्रधान, आरक्षक मनीष भोई का योगदान रहा।

एनजीटी के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्यवाही

जोहार छत्तीसगढ़-बेमेतरा।

कलेक्टर जितेन्द्र कुमार शुक्ला की अध्यक्षता में आज यहां जिला स्तरीय टास्ट फोर्स की बैठक आयोजित की गई। जिसमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल नई दिल्ली के निर्देशानुसार बेमेतरा जिले में गठित जिला स्तरिय टॉस्क फोर्स की बैठक में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बेमेतरा जसविन्दर कौर अजमानी मलिक, क्षेत्रीय अधिकारी छग पर्यावरण संरक्षण मंडल भिलाई, विश्वास राव म्हस्के, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद बेमेतरा होरी सिंह ठाकुर सहित सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत जिला बेमेतरा उपस्थित थे। जिला स्तरीय टॉस्क फोर्स समिति की बैठक द्वारा निर्णय लिया गया कि सभी नगरीय निकायों में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने हेतु विशेष प्राथमिकता के साथ कार्यवाही किए जाने हेतु निर्देशित किया गयाए जिसे निरंतर निरीक्षण हेतु निर्देशित किया गया। तथा कचरा कलेक्शन करने वाले सफ ाई मित्रों बहनों को प्रोत्साहित किया जावे। निर्माण गतिविधियों से उत्पन्न निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु कार्य योजना बनाने अपशिष्ट को पृथक पृथक संग्रहित करने अपशिष्ट को ना जलाने नियमों के उप बंधुओं का पालन न करने वालों के विरुद्ध उपविधि बनाने पुराने मलबा स्थल को वैज्ञानिक तरीकों से कैंपिंग करने हेतु निर्देशित किया गया। बेमेतरा जिला के अंतर्गत नगरीय निकायों द्वारा परफ ॉर्मेंस इंडिकेटर्स 18 बिंदुओं के तहत् विस्तृत चर्चा किया गया सभी बिन्दुओं पर गंभीरता पूर्वक समय-सीमा में कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया। निजी हॉस्पिटल का निरीक्षण आगामी बैठक के पूर्व किया जावे, जिनका मेडिकल वेस्ट विधिवत निप्टान किये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे, साथ ही हॉस्पिटलों में फायर सेफ्टिकी व्यवस्था सुनिश्चित किया जावे, जिसका भी प्रतिवेदन आगामी बैठक में रखा जावे। नगर पंचायत देवकर क्षेत्र में एसटीपी स्थापना हेतु मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत देवकर द्वारा शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जावे। जिले के सभी शैक्षणिक संस्थाओं महाविद्यालयों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन तथा वृक्षारोपण के संबंध में स्कूली छात्र छात्राओं के मध्य बैनर व पोस्टर के माध्यम से जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। सभी दुकानदारों को प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग में समझाइश दिए जाने के साथ ही बाजारों में प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री की जब्ती, पेनाल्टी की कार्यवाही की जावे। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार ठोस अपशिष्टों का उचित अपवहन किए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही जिला पंचायत जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत स्तर से किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को नियमित रूप से मुख्यालय में रहने एवं प्रात: काल सफाई का निरीक्षण स्वयं करने निर्देश दिया गया। शादी हॉल कैटरर्स को चिन्हित कर एकल उपयोग के उपयोग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए हैं। प्लास्टिक के विकल्प के रूप में दोना पत्तलए एनजीटी के नियमों का उल्लंघन करने वाले पर कार्यवाही कर जुर्माना वसूलने हेतु निर्देशित किया गया। नगर में निदान 1100 के फ्लैक्स प्रदर्शित किया जावे। बैठक में कलेक्टर ने अनुपस्थित रहने वाले मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत मारो एवं नवागढ को शो-काज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

पिटियाझर गौठान का उद्घाटन अब तक नहीं

आश्रय के लिये मवेशियों का सड़क पर जमावड़ा, राहगीर हो रहे हलाकान

जोहार छत्तीसगढ़-महासमुंद।

मवेशियों को सुरक्षित रखने गौठान का निर्माण कराया गया है। लेकिन निर्मित गौठान का उद्घाटन नहीं हो पाया है। यही कारण है कि शहर में लावारिश मवेशियों ने सड़क को ही अपना गौठान बना लिया है। बारिश के बाद खेतों में फसल बोआई होने से मवेशी शहर की ओर रुख कर रहे हैं। पिछले तीन माह से शहर के मुख्य मार्ग के अलावा गली.मोहल्ले की सड़कों को मवेशियों ने गौठान बना लिया है। इससे राहगीर के साथ मोहल्ले के नागरिक भी परेशान हैं बावजूद पालिका का रवैया उदासीन है। जानकारी के अनुसार शहर का गौरव पथ कहा जाने वाला बीटीआई रोड देर शाम के बाद गौ पथ में तब्दील हो जा ता है। शास्त्री चौक से कलेक्टोरेट कॉलोनी तक यहां सड़क में जगह जगह मवेशी बैठ रहते हैं जिससे राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इधर इस मार्ग में स्ट्रीट लाइट नहीं होने से हादसे का भय भी बना रहता है जिसे लेकर भी प्रशासन उदासीन है।

कुर्मीपारा कांजी हाऊस में रखे जा रहे मवेशी

पालिका के अफ सरों का कहना है कि पिटियाझर में निर्मित गौठान का उद्घाटन नहीं होने से मवेशियों को कुर्मी पारा स्थित कांजी हाऊस में रखा जा रहा है। कांजी हाऊस छोटा होने से यहां कम संख्या में मवेशी रखे जाते हैं। पालिकाकर्मियों के अनुसार वर्तमान में यहां करीब दो दर्जन मवेशी रखे गए हैं। अफसरों का कहना है कि मवेशियों को रखने जगह का अभाव और चारा-पानी की दिक्कत है।

सब्जी बाजार में ग्राहक, व्यापारी मवेशी से परेशान

खेतों में फसल बोआई के बाद चारे पानी के लिए भटक रहे मवेशियों ने शहर की ओर रुख कर लिया है। सड़कों पर चारा नहीं मिलने से अधिकांश मवेशियों ने सब्जी बाजार में अपना डेरा जमा रखा है जिससे यहां के व्यापारी के साथ ग्राहक भी परेशान हैं। क्योंकि बाजार में घूम रहे मवेशी व्यापारी के पसरे में रखी सब्जियों पर या फिर ग्राहकों के थैले पर रखी सब्जियों पर मुंह मार रहे हैं। सुबह-शाम सब्जी व्यापारियों द्वारा भेजे जाने वाले कचरे से चारा मिल जाता है।

पिटियाझर में निर्मित गौठान के उद्घाटन के लिए अध्यक्ष से चर्चा हुई है। उद्घाटन के बाद मवेशियों को यहां रखा जाएगा। वर्तमान में मवेशियों को कुर्मीपारा स्थित कांजी हाऊस में रखा जा रहा है। शहर में बड़ी तादात में मवेशी है जिन्हें रख पाना संभव नहीं है। मवेशी पालकों को समझाइश देने के बाद भी वे मवेशी सड़क पर छोड़ रहे हैं।

आशीष तिवारी, सीएमओ
नगर पालिका महासमुंद

महासमुंद नगर पालिका से एक सभापति का हटना तय

बनना था 8 सभापति बना दिये गये 9, मांगा जा रहा है शासन से मार्गदर्शन

जोहार छत्तीसगढ़-महासमुद्र। नवनिर्वाचित नपाध्यक्ष राशि विभुवन महिला ने 16 अगस्त को नगर पालिका के कामकाज संचालन के लिए प्रेसिडेंट इन काउंसिल का गठन किया। पालिका मीडिया प्रभारी से इस तारीख को जारी समाचार अनुसार उन्होंने इसमें सात पार्षदों को सभापति बनाया गया। वहीं नगर पालिका के सात विभाग के लिए पांच-पांच पार्षदों के समूहों का सलाहकार समिति के सदस्य नियुक्त किया गया।

महिलांग ने प्रभारी सदस्यों को विभाग आवंटित कर प्रभारी सदस्य नियुक्त किया जिसमे वार्ड नंबर 12 के पार्षद पर मांझी को विधि तथा समान्य प्रशासन विभाग का सभापति वार्ड 29 के पार्षद निखिल साहू को आवास पर्यावरण एवं लोक निर्माण के पार्षद व पूर्व पालिका पटेल जल कार्य विभाग का सभापति वार्ड 18 के पार्षद अमन चढ़ाकर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग वार्ड नंबर के पार्षद बबलू हरपाल राजस्व तथा बाजार विभाग वार्ड 17 के पार्षदमा अन्य यादव खाद्य नागरिक आपूर्ति नियोजन विभाग और वार्ड 14 के पार्षद सरला गोलू मदनकार को शिक्षा महिला एवं बाल विकास विभाग का सभापति बनाया गया। इसमें वार्ड तीन के पार्षद उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार चटाकर का नाम न होने से पैचस गया। नियमतः अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को मिलाकर प्रेसिडेंट इन कौंसिल में कल आठ सदस्य होता है। सात नए सदस्यों को मौका देने से नी हो गई है।

इस संबध में अब पालिका अधिकारी शासन से मार्गदर्शन में रहे है। आगामी दिनों में इस पर निर्णय लिया जाएगा। यदि संख्या आठ से आगे नहीं बरती तो किश को सात नए सभापतियों में से एक को हटाना होगा। फ्लिहाल इस पर पार्टी संगठन है।

कौन हटेगा इस पर नगर में चर्चा का दौर

पालिका अधिनियम के जानकारी का कहना है कि इस मै अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के अतिरिक्त यह और सदस्य होते हैं। संख्या एक बढ़ गई है। ऐसे में किसे सभापति पद से हटाएंगी इस पर नगर में कवास का दौर जारी है। सभापति बनाये गए सदस्यों में पर गांधी आदिवासी वह से है और निर्दलीय चुनाव जीतकर आये है। निखिलका साहू कामेस के युवा चेहरा हैए सर्वाधिक मतों से इन्होंने चुनाव जीता है। पटेल पूर्व परिहे है साथ ही तीन माह के राजनी पटना में भाजपा से निष्कासित हुए हैं। अमन पाकर युद्ध कांग्रेस के जिलाध्यक्ष है। बबलू हरपाल निर्दलीय पार्षद जीतकर आये है। अनुसूचित जाति वर्ग को प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्होंतिक बंदर के पीआईसी सदस्य होते हुए सभापति पद छोड़कर और खाली कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सीमा अजय यादव जाम आदमी पार्टी की पार्षद है और नया बनाने में कार्य का भरपूर साथ दिया है। सरला गोनू मदनकार छोड़कर आई है। पालिका की सीट पर भाजपा की अध्यक्ष बिठाने में इनकी भूमिका रही है।

सभापति सूची में उपाध्यक्ष का नाम भूलवर्ष छूट गया था। शासन से मार्गदर्शन लिया जा रहा है। दो दिनों में तय कर संशोधित सूची जारी की जाएगी।

राशि महिलांग, नपाध्यक्ष महासमुंद

कानून का पालन कराना सीएमओ का दायित्व नियम कानून का पालन कराना सीएमओ का पदीय कर्तव्य है। राजपत्र में उल्लेख है की पदेन उपाध्यक्ष पीआईसी सदस्य रहेगा। फिर उपाध्यक्ष को पीआईसी दर से दरकिनार किया जाना नियम विरूद्ध है। सीएमओ को निलंबित करने पत्र लिखेंगे।

कृष्ण कुमार चंद्राकर
उपाध्यक्ष नगर पालिका महासमुंद

जनचौपाल के दौरान सुनी गई आम नागरिकों की समस्याएं

जोहार छत्तीसगढ़-बेमेतरा।

संयुक्त जिला कार्यालय कलेक्टोरेट परिसर में प्रत्येक मंगलवार को आयोजित आम जनता से साप्ताहिक भेंट मुलाकात कार्यक्रम जनचौपाल के दौरान कलेक्टर जितेन्द्र कुमार शुक्ला के निर्देश पर जिला पंचायत सीईओ लीना कमलेश मण्डावी ने आज जिले के विभिन्न गांवों से आये आम नागरिकों की समस्याएं सुनी और उनके निराकरण के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

कलेक्टोरेट के दृष्टि सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक जनचौपाल के दौरान बेमेतरा जिले के विभिन्न गांवों से आये आम नागरिकों ने विभिन्न विभागों से संबंधित 18 आवेदन प्रस्तुत किये। प्राप्त आवेदनों में राशन कार्ड बनाने, समूह की ऋण माफी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिलाये जाने, स्वामी आत्मानंद स्कूल में प्रवेश हेतु, शासकीय भूमि में अतिक्रमण हटवाने, सहायता राशि प्रदान करने आदि से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। सीईओ ने संबंधित अधिकारियों को समय सीमा के भीतर आम लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश दिए। जिला पंचायत सीईओ ने कहा कि जिन मामलों में आवेदनों का निराकरण नियमानुसार संभव नहीं है उस पर आवेदक को पृथक से लिखित रुप में सूचना भी दी जाए। इस अवसर पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बेमेतरा युगल किशोर उर्वशा नवागढ़ प्रवीण तिवारी, बेरला संदीप ठाकुर, डिप्टी कलेक्टर विश्वास राव म्हस्के, परियोजना अधिकारी मबावि बीडी पटेल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

सीएम के जन्म दिन पर दीर्घायु की आहुती के साथ वस्त्र दान

जोहार छत्तीसगढ़-देवभोग।

सीएम के ऐसे भी शुभचिंतक है जिन्होंने ने आज जन्मदिन पर दीर्घायू ही नही सतत सरकार में बने रहने कराया महायज्ञ, पंडितों को भोजन करवा सीएम से वर्चुवल जुड़ आशीर्वाद भी दिलवाया। प्रदेश भर में सीएम भूपेश बघेल का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। पर गरियाबन्द जिले में भाजपा का गढ़ माने जाने वाले बिन्द्रानवागढ़ में कांग्रेस नेताओं द्वारा कराया गया विष्णु महायज्ञ सीएम को भी गया। कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष सुखचन्द बेसरा ने इस यज्ञ का आयोजन स्थानीय जगन्नाथ मंदिर में करवाया। स्थानीय नागरिक संगठन के वरीष्ठ जन के अलावा सीएम हाउस के करीब माने जाने वाले महासमुंद के कांग्रेसी नेता आलोक चन्द्राकर भी यज्ञ में आहुति देने पहुंचे थे। पूजन सम्पन्न के बाद सीएम के 61 वे जन्मदिन में 61 ब्राम्हणों को भोजन कराने के अलावा अन्य आगन्तुकों को भंडारे लगा कर भोजन दिया गया। गरीब महिलाओं को वस्त्र दान भी किये गए। आयोजन में पहुंचे सभी को केक के साथ कांग्रेस सरकार के योजनाओं की जनाकारी देने वाले किताबे पाम्पलेट का भी वितरण किया गया।

पूर्णाहुति के बाद आलोक चन्द्राकर ने सीएम को वर्चुवली जोड़ा, जिसके जरिये सीएम ने पंडितों के आशीर्वाद के अलावा शुभचिंतको का शुभकानाएं ग्रहण कर सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। आयोजन में महेश्वर कोमर्रा, खिलावन पात्र, राजेश तिवारी, धनसिंह मरकाम, राजेश तिवारी, जय कुमार, कुंजल राम यादव, विकास अग्रवाल, अर्जुन अग्रवाल, धनेश्वर प्रधान, टिकेंद्र बीसी, नवीन सेन, निराकार डोंगरे, ओंकार पात्र आदि प्रमुख रूप से शामिल थे।

बम्हनी सरपंच पर अनियमितता का आरोप, कलेक्टर से पंचों ने की जांच की मांग

जोहार छत्तीसगढ़-महासमुंद।

बम्हनी सरपंच पर पंचों ने पंचायत की मूलभूत राशि और 14 वें तथा 15 वें वित्तीय की राशि आहरित कर अनियमितता का आरोप लगाया है। इसकी शिकायत पंचों ने मंगलवार को जिला कार्यालय में की है। पंच सोनिया कोसरे, फ लेन्द्र निषाद, गोविंद महिलांग, कामता प्रसाद सोनवानी और पुरुषोत्तम साहू ने कलेक्टर के नाम कुल 10 बिंदुओं में जांच के लिए ज्ञापन सौंपा है। उनके द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में पंचों ने कहा है कि सरपंच द्वारा पंचायत के मूलभूत एवं 14 व 15 वें वित्त की राशि को मनमाने तरीके से आहरित कर विकास कार्य में लगाने की बजाए दुरुपयोग किया गया है। अपने निजी लाभ के लिए राशि खर्च कर गांव के विकास कार्य पर प्रतिकूल असर डाला गया है। पंचों को बिना विश्वास में लेकर कार्य किया जा रहा है। उन्होंनें सरपंच की जगह पंचायत का कार्य पूरी तरह से पति द्वारा किए जाने का भी आरोप लगाया है। इधर मामले में सरपंच खिलेश्वरी साहू का कहना है कि पंचों द्वारा की गई शिकायत गलत है। उनके द्वारा रुपए की मांग की जाती है। नहीं देने पर यह आरोप लगाया जा रहा है।

एक नजर

रायपुर में होगी अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन

जोहार छत्तीसगढ़-बेमेतरा।

भारतीय थलसेना द्वारा छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी हेतु अग्निवीर की भर्ती रैली का आयोजन रायपुर में किया जा रहा है। इस भर्ती रैली में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थी को थलसेना की वेबसाईट में ऑनलाईन पंजीयन आवेदन करना अनिवार्य है। यह ऑनलाईन पंजीयन की प्रक्रिया 3 सितम्बर 2022 तक किया जा सकता है। ऑनलाईन पंजीयन करने के पश्चात् प्रवेश पत्र जिसमें रैली स्थल, समय की जानकारी आपकी पंजीकृत ईमेल में 5 नवम्बर 2022 तक भेजा जावेगा। रैली हेतु अभ्यर्थियों के पास आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक खाता, ई-मेल आईडी, मोबाईल नंबर होना अनिवार्य है। भर्ती रैली निःशुल्क है, चयन आपकी अर्हता योग्यता एवं भर्ती रैली में प्राप्त अंको के वरिष्ठता क्रम के आधार पर होगा। अधिक जानकारी हेतु सेना भर्ती कार्यालय रायपुर के दूरभाष 07712965213 या जिला रोजगार कार्यालय, बेमेतरा के दूरभाष 07824222665 या भारतीय थलसेना के वेबसाईट से प्राप्त कर सकते है। भर्ती रैली में सम्मिलित होने हेतु अभ्यार्थी को ऑनलाईन पंजीयन नामांकन अनिवार्य है।

मुख्यमंत्री निवास घेरने महासमुंद ग्रामीण क्षेत्र से शामिल होंगे सैकड़ों युवक

जोहार छत्तीसगढ़-महासमुंद।

भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा महासमुंद ग्रामीण मण्डल की बैठक जिला भाजपा कार्यालय में हुई। बैठक में 24 अगस्त के लिए, रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में ग्रामीण मण्डल के 56 गांवों से युवा और भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। लगभग 400 कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई। घेराव युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में होगा। ग्रामीण मण्डल की बैठक में प्रभारी एवं पूर्व विधायक व चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक डॉ विमल चोपड़ा, पूर्व जिला पंचायत सदस्य मोती साहू, पार्षद देवीचंद राठी, मण्डल अध्यक्ष श्याम साकरकर, पूर्व मण्डल अध्यक्ष प्रेम चंद्राकर, युवा मोर्चा मण्डल अध्यक्ष यशवंत साहू युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष आनंद साहू, वरिष्ठ नेता हेमलाल चंद्राकर उपस्थित रहे। बैठक में प्रभारी एवं पूर्व विधायक डॉ विमल चोपड़ा ने अपने उद्बोधन में बेरोजगार युवाओं को हक की लड़ाई बताई। रूपरेखा तैयार करने के पश्चात निर्णय लिया गया कि महासमुंद ग्रामीण मण्डल से 400 युवा प्रदर्शन में शामिल होंगे। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व जिला पंचायत सदस्य व वरिष्ठ भाजपा नेता मोती साहू ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आने के पूर्व छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं को 2500 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया और सत्तासीन होने के बाद वादा से मुकर गई। अभी तक किसी प्रकार बेरोजगारी भत्ता मिला और न ही रोजगार। भाजपा युवा मोर्चा के मण्डल अध्यक्ष यशवंत साहू ने कहा कि वे अपने हक की लड़ाई लड़ें जो भारतीय श्जनता पार्टी के नेतृत्व में रायपुर में की जाएगी। बैठक के दौरान जिले के ग्रामीण मण्डल से मेघनाथ चन्द्रसेन, गोविंद ठाकुर, मुकेश ध्रुव, हेमलाल यादव, पूनम मिश्रा, नानिकराम निषाद, प्रकाश रात्रे, पितांबर साहू, राजू साहू, लोकनाथ साहू, नन्दलाल पटेल, नवीन साहू, देवेन्द्र सेन, पलाश यादव, मुकेश यादव, पिंकू यादव, नमन यादव, युगल किशोर, दिलीप सिन्हा, परस साहू, जय साहू, कृष्णा साहू एवं अन्य युवा उपस्थित रहे।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्राम राम्हेपुर में किया जा रहा नल कनेक्शन

कवर्धा । विकासखंड बोडला के ग्राम राम्हेपुरकला की जनसंख्या 1245 है। विभाग द्वारा पेयजल व्यवस्था के तहत 12 हैण्डपंप स्थापित है, सिंगलफेस पावरपंप 7 संचालित एवं 1 नग सोलर पंप संचालित है तथा नल जल योजना के तहत 60 कि.ली क्षमता एवं 12 मीटर स्टेजिंग की उच्चस्तरीय जलागार स्थापित है।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंता ने बताया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्य प्रगतिरत है। उन्होंने बताया कि 540 नग घरेलू नल कनेक्शन दिया जाना प्रस्तावित है एवं कार्य प्रगतिरत है। वर्तमान में ग्राम राम्हेपुर में 260 कनेक्शन दिया जा चुका है एवं शेष घरों में कनेक्शन प्रदाय का कार्य प्रगतिरत है। उन्होंने बताया कि लगातार बारिश के कारण नवीन पाईपलाईन बिछाने का कार्य विलंब हुआ है। वर्तमान में कार्य में प्रगति लाई गई है। ग्राम में पेयजल व्यवस्था सामान्य है।

ग्राम दौजरी में पेयजल के लिए की गई व्यवस्था

कवर्धा । विकाखंड कवर्धा अंतर्गत ग्राम दौजरी के शिव मंदिर के पास ग्राम पंचायत द्वारा बोर में हैंण्डपंप लगाया गया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंता ने बताया कि वर्तमान में हैंण्डपंप चालू हालत में है तथा पेयजल की कोई समस्या नहीं है।

छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के सदस्य अपने दो सूत्रीय मांग को लेकर बैठे अनिश्चितकालीन धरने पर

जोहार छत्तीसगढ़-धरमजयगढ़।

सीतापुर कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के सदस्य छत्तीसगढ़ शासन से अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं।

अपनी 2 सूत्रीय मांग को लेकर कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन छत्तीसगढ़ द्वारा पहले भी तीन-चार बार धरना प्रदर्शन किया जा चुका है। परंतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इनकी मांगों को अभी तक पूर्ण रूप से नहीं माना गया है। इस कारण वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं, उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ शासन जब तक उनकी मांगों को पूर्ण नहीं करती तब तक हड़ताल का समापन नहीं करेंगे। केंद्र सरकार के समान देय तिथि से 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता तथा सातवें वेतनमान में गृह भाड़ा भत्ता दिया जाए। इन मांगों को लेकर आज लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में सीतापुर के सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित हुएए तथा उनके द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल का आयोजन किया गया। जब हमने इस विषय पर वहां के पदाधिकारियों से बात हुई तो उनके द्वारा कहा गया कि राज्य शासन द्वारा वादा किया गया था कि उनकी मांगों को पूरा करेगा। परंतु वह छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों अधिकारियों से वादाखिलाफी कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार उनकी समुचित मांगों को पूर्ण नहीं कर रही है, जिससे छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों अधिकारियों में छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ काफी ज्यादा रोष है, उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कर्मचारियों अधिकारियों के हितों का ध्यान रखते हुए उनकी मांगों को पूर्ण कर देना चाहिए, और यदि उनके द्वारा मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो अधिकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहेंगे।

लोहारडीह बांध के फूटने पर साढे 5 सौ एकड़ की फसल होगी चौपट

4 माह पूर्व ही सवा करोड़ की लागत पर हुआ था बांध का जीर्णोद्धार

जोहार छत्तीसगढ़-महासमुंद।

रिसाव रोकने किसान कर रहे अथक प्रयास

जिले में इस साल अच्छी बारिश के चलते जिले के छोटे-बड़े लगभग सभी बांध लबालब हैं। इन्हीं में से एक लोहारडीह ग्राम पंचायत का बांध भी है। जिसकी क्षमता 0.99 एमसीएम है और 308 हेक्टेयर की भूमि में इससे सिंचाई होती है। लगातार हो रहा बारिश से ये बांध 100 फीसदी भर चुका है। इस बीच लोहारडीह के बांध में पिछले एक हफ्ते से गेट वॉल प्लेटफार्म के पास से पानी का रिसाव हो रहा है। जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। दरअसल, किसानों की चिंता इस बात को लेकर है कि यदि ये बांध फूट जाता है तो 350 किसानों की 550 एकड़ में फैली फसल चौपट हो जाएगी, इसे लेकर किसान वहां मजदूरी कर बांध के रिसाव को रोकने में लगे हैं। जबकि सिंचाई विभाग ने चार महीने पहले ही इस बांध के जीर्णोधार में 1 करोड़ 30 लाख रुपये खर्च किए थे। लेकिन इसके बावजूद पानी का रिसाव हो रहा है। लिहाजा ग्रामीण सिंचाई विभाग पर गुणवत्ताहीन कार्य कराने का आरोप लगा रहे हैं।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक नारायण बाईन, द्वारा आसमा पब्लिसर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,जयस्तंभ चौक रायपुर से मुद्रित कर मेडरमार कालोनी, जिला-रायगढ़ (छत्तीसगढ़) से प्रकाशित।
संपादक -**नारायण बाईन,** फोन -फैक्स 07766299001, मो, 9479177711, 7489419194 Email-joharchhattisgarh@gmail.com, joharchhattisgarh@yahoo.co.in